

जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बनाम

बौद्धिक संपदा अपील्य बोर्ड और अन्य

(सिविल अपील सं.430/2016)

20 जनवरी, 2016

(कुरियन जोसेफ और आर.एफ. नरीमन, न्यायाधिपति)

व्यापार और वाणिज्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1999: धारा 125-प्रयोज्यता-प्रतिवादी क्रमांक 4 की, जो मादक पेय के निर्माण और विपणन में लगा हुआ है और अपने लाइसेंसधारी 'सीग्राम' के माध्यम से ट्रेडमार्क 'ब्लेंडर्स प्राइड' को अपनाने का दावा करता है- उक्त ट्रेडमार्क का पंजीकरण 50 देशों में प्रदान किया गया था, भारत में पंजीकरण के लिए आवेदन लंबित था- अपीलकर्ता ने समान ट्रेडमार्क 'ब्लेंडर्स प्राइड' के पंजीकरण के लिए आवेदन किया- प्रतिवादी संख्या 4 ने विरोध का नोटिस दायर किया- हालांकि, प्रतिवादी संख्या 4 ने पाया कि पंजीकरण प्रमाणपत्र अपीलकर्ता को जारी किया गया था- प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा रिट याचिका- इस बीच कारण बताओ नोटिस रजिस्ट्रार द्वारा धारा 57(4) के तहत रजिस्ट्रार को सुधारने का प्रस्ताव जारी किया गया- कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए रजिस्ट्रार को निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा किया गया- इस बीच प्रतिवादी संख्या 4 के लाइसेंसधारी के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया- जबकि रजिस्ट्रार ने निशान हटाकर रजिस्ट्रार/धारा 57(4) में सुधार करने का प्रस्ताव दिया- पीड़ित अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार को उसके समक्ष कार्यवाही का निपटान करने का निर्देश दिया- रजिस्ट्रार ने यह कहते हुए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को वापस ले लिया कि उसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है धारा

125 के आधार पर आगे बढ़ने का और कार्यवाही केवल अपीलीय बोर्ड के समक्ष जारी रह सकती है- अपीलीय बोर्ड ने माना कि जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तो लाइसेंसधारक ने अभी तक अपना जवाबी बयान दाखिल नहीं किया था क्योंकि उसे मुकदमे के कागजात भी नहीं दिए गए थे और चूंकि मुकदमा प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ दायर नहीं किया गया था, बल्कि केवल लाइसेंसधारी के खिलाफ दायर किया गया था धारा 125 में कोई आवेदन नहीं होगा और इसलिए रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द करना होगा रजिस्ट्रार को विपक्षी कार्यवाही पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया- अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर की- उच्च न्यायालय ने माना कि मामले की नए सिरे से सुनवाई का निर्देश देने में अपीलीय बोर्ड द्वारा कोई अन्याय नहीं किया गया- माना गया : धारा 124(1) केवल उल्लंघन के मुकदमे के वादी और प्रतिवादी को संदर्भित करता है, और धारा 124(1)(ii) विशेष रूप से "संबंधित पक्ष" को संदर्भित करता है जो रजिस्टर के सुधार के लिए अपीलीय बोर्ड को आवेदन करेगा- इसी तरह, धारा 125 भी पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मुकदमे में केवल "वादी और "प्रतिवादी" को संदर्भित करता है- इसलिए, यह स्पष्ट है कि रजिस्टर के सुधार के लिए आवेदन या तो प्रतिवादी द्वारा किया जा सकता है जो इसमें याचिका उठाता है मुकदमा करें कि वादी के ट्रेडमार्क का पंजीकरण अमान्य है, या वादी द्वारा जो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के ट्रेडमार्क के पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाता है, जहां प्रतिवादी बचाव / धारा 30(2)(ई) अन्तर्गत उठाता है- इसलिए यह स्पष्ट है धारा 125(1) में निर्दिष्ट रजिस्टर के सुधार के लिए आवेदन केवल उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन (वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए) हो सकता है- प्रतिवादी लाइसेंसधारी है, यह स्पष्ट है कि अनुभाग में कोई आवेदन नहीं होगा- प्रतिवादी संख्या 4 को उक्त मुकदमे में प्रतिवादी पक्ष नहीं बनाया गया है- साथ ही, संबंधित ट्रेडमार्क के पंजीकरण की वैधता के मुद्दे को रजिस्टर के सुधार के लिए आवेदन में निर्धारित किया जाना है, जो स्पष्ट

रूप से केवल मुकदमे के पक्षों को बाध्य करेगा और किसी को नहीं। इन कारणों से, सुधार के लिए आवेदन, उक्त मुकदमे में किसी भी पक्ष प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन के लिए नहीं किया गया और धारा 125(1) के पारित होने का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

उपधारा 21(2), 23(1) पंजीकरण का विरोध- 7 अक्टूबर 2003 को जर्नल में प्रकाशित विवादित ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन- प्रतिवादी संख्या 4 ने 6.1.2004 को विरोध का नोटिस दाखिल करने के लिए एक महीने के समय के विस्तार की मांग की- 19.1.2004 को, प्रतिवादी संख्या 4 ने विरोध का नोटिस दायर किया- 16.2.2004 को, ट्रेड मार्क रजिस्ट्री ने अपीलकर्ता को एक नोटिस जारी किया जिसमें विरोध के उक्त नोटिस पर अपना प्रति कथन आमंत्रित किया गया और कहा गया कि यदि प्रति कथन दाखिल नहीं किया गया समय के भीतर, ट्रेड मार्क को त्याग दिया हुआ माना जाएगा 20.1.2005 को, प्रतिवादी संख्या 4 को पता चला कि ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाण पत्र अपीलकर्ता को 13.1.2004 को ही जारी किया गया था- माना गया: रजिस्ट्रार द्वारा समय बढ़ाया गया था जैसा कि साक्ष्य द्वारा दिया गया है पत्र दिनांक 16.2.2004- इसलिए, 6.1.2004 से 30 दिनों की विस्तारित अवधि से पहले दिया गया कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारा 23(1) का उल्लंघन होगा- इसलिए, 13.1.2004 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र धारा 23(1)(ए) का उल्लंघन होगा और उक्त ट्रेडमार्क को वहां से हटाकर रजिस्ट्रार को ठीक करना होगा।

धारा 57(4)-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार- बॉम्बे में रजिस्ट्रार द्वारा जारी धारा 57(4) के तहत कारण बताओ नोटिस- दिल्ली में बने व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन- दलील कि कारण बताओ नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना था- माना गया: अधिनियम की धारा 57(4) के तहत, स्वतः संज्ञान की शक्ति का प्रयोग केवल रजिस्ट्रार द्वारा ही काम में ली जा सकती है, जो कि उक्त धारा की उपधारा (1) और (2) में संदर्भित "न्यायाधिकरण" है, इसलिए, होने की शक्ति धारा 57(4) के तहत शक्ति का प्रयोग

केवल ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसा केवल एक रजिस्ट्रार है और उसका पंजीकृत कार्यालय बॉम्बे में है- दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में सहायक रजिस्ट्रार सभी इसके तहत कार्य करते हैं रजिस्ट्रार, बॉम्बे के अधीक्षण और निर्देश, जैसा कि अधिनियम की धारा 3(2) से स्पष्ट है लेकिन इसके तहत कार्य करते हैं, इसलिए, यह दलील कि बॉम्बे में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना था, निरर्थक था।

न्यायालय अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1. प्रतिवादी संख्या 4 ने धारा 21(2) के तहत दी गई तीन महीने की अवधि के भीतर विरोध का नोटिस दाखिल करने के लिए एक महीने के समय के विस्तार की मांग की और ऐसा निर्धारित वैधानिक फॉर्म टीएम-44 में यह कहते हुए किया कि विस्तार का कारण यह होगा कि उन्हें विरोध का नोटिस दाखिल करने से पहले कानूनी सलाह लेनी होगी। दिनांक 19.1.2004 के विरोध का नोटिस एक महीने की विस्तारित अवधि के भीतर दिया गया था, और रजिस्ट्रार द्वारा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर लिया गया था, जैसा कि रजिस्ट्रार के पत्र दिनांक 16.2.2004 में दर्शाया गया है। इस पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि विपक्ष के नोटिस को रिकार्ड में ले लिया गया था। ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि एक महीने का समय नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि विरोध का उक्त नोटिस केवल 19.1.2004 को दायर किया गया था, यानी 6.1.2004 को तीन महीने खत्म होने के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर। हालाँकि अधिनियम की धारा 131 रजिस्ट्रार की संतुष्टि को संदर्भित करती है और उन शर्तों को संदर्भित करती है जिन्हें वह लागू करना उचित समझ सकता है, यह स्पष्ट है कि यदि वह समय बढ़ाना चाहता है तो उसे हर मामले में एक अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार द्वारा समय बढ़ाया गया है, जैसा कि दिनांक 16.2.2004 के पत्र से प्रमाणित है। इसलिए, 6.1.2004 से 30 दिनों

की विस्तारित अवधि से पहले दिया गया कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 23(1) का उल्लंघन होगा। मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलीय बोर्ड और खंड पीठ यह घोषित करने में स्पष्ट रूप से सही हैं कि 13.1.2004 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र धारा 23(1)(ए), उल्लंघनकारी होगा और उक्त ट्रेडमार्क को वहां से हटाकर रजिस्टर को ठीक करना होगा। [अनुच्छेद 15, 16, 18] [825- सी-डी; 826-ई-एफ; 828-बी-एफ)

2. याचिका में कहा गया था कि धारा 57(4) के तहत दिनांक 16.2.2005 का कारण बताओ नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि यह बॉम्बे में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया था, न कि दिल्ली में अधिकारियों द्वारा और क्योंकि ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया था दिल्ली में और उसके बाद की सभी कार्यवाही दिल्ली में हुई, यह कारण बताओ नोटिस भी दिल्ली में ही जारी किया जाना चाहिए था। अधिनियम की धारा 57(4) के तहत, स्वतः संज्ञान की शक्ति का प्रयोग केवल रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जा सकता है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) और (2) में संदर्भित "न्यायाधिकरण " है। इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा 57(4) के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग केवल ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसा केवल एक ही रजिस्ट्रार है- और उसका पंजीकृत कार्यालय बंबई में है। दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में सहायक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार, बॉम्बे के अधीक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करते हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 3(2) से स्पष्ट है। अतः यह बात निरर्थक है। [अनुच्छेद 19,20,21] [828-जी-एच; 829-सी-डी]

3.1. अधिनियम की धारा 124 में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि जहां, ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मुकदमे में, प्रतिवादी दलील देता है कि वादी के ट्रेडमार्क का पंजीकरण अमान्य है, तो मुकदमे की सुनवाई करने वाली अदालत सुधार कार्यवाही के अंतिम निपटान तक मुकदमे पर रोक लगाएगी रजिस्ट्रार या अपीलीय बोर्ड के समक्ष,

जैसा भी मामला हो। धारा 124 के तहत योजना धारा 125 के दायरे को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि जहां उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर करने से पहले रजिस्टर के सुधार की कार्यवाही लंबित है जिसमें प्रतिवादी का अनुरोध है कि वादी के ट्रेडमार्क का पंजीकरण अमान्य है, ऐसी कार्यवाही अधिनियम की धारा 57(1) और (2) के मद्देनजर या तो रजिस्ट्रार के समक्ष या अपीलीय बोर्ड के समक्ष की जा सकती है। लेकिन, यदि उल्लंघन के लिए ऐसे मुकदमे दायर करने के बाद सुधार की कार्यवाही शुरू की जानी है जिसमें प्रतिवादी यह दलील देता है कि वादी के ट्रेडमार्क का पंजीकरण अमान्य है, तो सुधार की कार्यवाही केवल अपीलीय बोर्ड के समक्ष ही की जा सकती है और रजिस्ट्रार के समक्ष नहीं। [अनुच्छेद 22 और 23] [829-ई-जी]

3.2. धारा 124(1) केवल उल्लंघन के मुकदमे के वादी और प्रतिवादी को संदर्भित करता है, और धारा 124(1)(ii) विशेष रूप से "संबंधित पक्ष" को संदर्भित करता है जो रजिस्टर के सुधार के लिए अपीलीय बोर्ड पर आवेदन करेगा। इसी प्रकार, धारा 125 भी पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मुकदमे में केवल "वादी" और "प्रतिवादी" को संदर्भित करती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि रजिस्टर में सुधार के लिए आवेदन या तो प्रतिवादी द्वारा किया जा सकता है जो मुकदमे में दलील देता है कि वादी के ट्रेडमार्क का पंजीकरण अमान्य है, या वादी द्वारा जो पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का ट्रेडमार्क, जहां प्रतिवादी धारा 125(1) में निर्दिष्ट रजिस्टर की धारा के तहत बचाव करता है, केवल उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन (वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए) हो सकता है। प्रतिवादी सीग्राम है और प्रतिवादी संख्या 4 नहीं है, यह स्पष्ट है कि धारा का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। यह प्रस्तुत करना कि सीग्राम केवल प्रतिवादी संख्या 4 का लाइसेंसधारी है और दोनों पक्षों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एक ही हैं, इस कारण से कोई औचित्य नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 को अपीलकर्ता के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं कहा जाता है।

सीग्राम फिर से दो अलग-अलग कंपनियां बन गईं। वाद में आरोप है कि उक्त दोनों कंपनियां शराब के निर्माण और वितरण में लगी हुई थीं और ट्रेडमार्क "ब्लैंडर्स प्राइड" के तहत मादक पेय बेचती और निर्यात करती थीं, जो वादी का पंजीकृत ट्रेडमार्क है। वादपत्र में यह नहीं बताया गया है कि पहला और दूसरा प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 4 के उक्त ट्रेडमार्क के लाइसेंसधारी थे। वास्तव में, वाद के पैराग्राफ 10 में, वादी द्वारा एक विशिष्ट कथन था कि आवश्यक पूछताछ करने पर, वादी को पता चला है कि प्रतिवादियों ने अपने पक्ष में ट्रेडमार्क 'ब्लैंडर्स प्राइड' के पंजीकरण के लिए आवेदन भी नहीं किया है। यह मुकदमा उल्लंघन के साथ-साथ पारित करने का भी मुकदमा है, और प्रतिवादी संख्या 4 को उक्त मुकदमे में प्रतिवादी पक्ष नहीं बनाया गया है। साथ ही, संबंधित ट्रेडमार्क के पंजीकरण की वैधता के मुद्दे को रजिस्टर के सुधार के लिए आवेदन में निर्धारित किया जाना है, जो स्पष्ट रूप से केवल मुकदमे के पक्षों को बाध्य करेगा और किसी को नहीं। इन कारणों से, सुधार के लिए आवेदन, उक्त मुकदमे में किसी भी पक्ष प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन के लिए और पारित करने के लिए नहीं किया गया है, धारा 125(1) की कोई प्रयोजता नहीं होगी। दूसरा खंड पीठ उच्च न्यायालय का यह तर्क भी सही था कि धारा 125(1) ए केवल रजिस्टर के सुधार के लिए आवेदनों पर लागू होगी, न कि धारा 57(4) के तहत रजिस्ट्रार की स्वतः प्रेरणा शक्तियों के प्रयोग पर। कारण खोजना कठिन नहीं है। यदि रजिस्ट्रार को रजिस्टर की शुद्धता बनाए रखने के लिए धारा 57(4) के तहत स्वतः संज्ञान लेने से रोक दिया गया है, तो ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहां प्रतिवादी, उल्लंघन के मुकदमे में अमान्यता की दलील देने के बाद, आगे नहीं बढ़ने का विकल्प चुनता है अपीलीय बोर्ड के समक्ष सुधार याचिका दाखिल करने के साथ आगे नहीं बढ़ने का विकल्प चुनता है। [अनुच्छेद 24,25] [829-एच; 830-ए-एच; 831-ए-बी]

4. धारा 47(4) को धारा 107 में इस कारण से संदर्भित किया गया था कि उक्त उपधारा एक रक्षात्मक ट्रेडमार्क के रूप में ट्रेडमार्क के पंजीकरण को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय या रजिस्ट्रार को किए गए आवेदनों को संदर्भित करती है। धारा 47 के अन्य उप-भाग ऐसे किसी भी आवेदन का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि केवल यह बताते हैं कि रक्षात्मक ट्रेडमार्क का क्या मतलब है, और यही कारण है कि धारा 107 केवल धारा 47(4) को संदर्भित करती है, न कि संपूर्ण धारा 47 को। हालाँकि, ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 125(1) में, अभिव्यक्ति "धारा 57" की दायरा "और रजिस्टर के सुधार के लिए एक आवेदन" अभिव्यक्ति द्वारा कम कर दी गई है। ऐसे सुधार आवेदन केवल धारा 57(1) और (2) के संदर्भ में हैं, न कि धारा 57(4) के तहत रजिस्ट्रार की स्वतः प्रेरणा शक्ति के लिए। इसलिए, रजिस्टर की शुद्धता बनाए रखने के ऊपर दिए गए ठोस कारण के अलावा, धारा 125(1) की शाब्दिक संरचना पर भी, यह स्पष्ट है कि धारा 57(4) को बाहर करना होगा। [अनुच्छेद 26] [832-जी-एच; 833-ए-बी] सी ई

व्हेलपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, मुंबई और अन्य 1998 (2) पूरक एससीआर 359: (1998) 8 एससीसी 1; एम. मजहरुद्दीन अली बनाम सरकार एपी, (2000) 10 एससीसी 383- लागू नहीं होने योग्य ठहराया गया

हार्डी ट्रेडिंग लिमिटेड और अन्य बनाम एडिसन पेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड 2003 (3) पूरक एससीआर 686: (2003) 11 एससीसी 92; कैलाश बनाम नन्हकु 2005 (3) एससीआर 289: (2005) 4 एससीसी 480 पर निर्भर किया।

मेसर्स एलाइड ब्लैंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई बनाम बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, चेन्नई एवं अन्य एआईआर 2009 मद्रास 196 का संदर्भ दिया गया।

केस लॉज संदर्भ

1998 (2) पूरक एससीआर 359	अनुपयुक्त ठहराया	अनुच्छेद 10
2003 (3) पूरक एससीआर 686	निर्भर किया	अनुच्छेद 11
एआईआर 2009 मद्रास 196	संदर्भित	अनुच्छेद 16
(2000) 10 एससीसी 383	अनुपयुक्त ठहराया	अनुच्छेद 17
बी 2005 (3) एससीआर 289	निर्भर किया	अनुच्छेद 17

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 430/2016

पत्र पेटेंट अपील संख्या 245/2008 में दिल्ली के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.01.2009 से।

अपीलकर्ता के लिए प्रतिभा एम. सिंह, कमल बुद्धिराजा, वैभव एम., अमन गुप्ता, निखिता, देव्यांशु, अभिनव मुखर्जी उत्तरदाताओं के लिए।

सुधीर चंद्र, ए. के. सांघी, हेमंत सिंह, ममता झा, मनीष के.मिश्रा, वसीम शुएब अहमद, सुरुची अग्रवाल, निखिल मजीठिया, एस. एस. रावत, रश्मि मल्होत्रा, डी. एस. माहरा उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

आर. एफ. नरीमन, न्यायाधिपति।

अनुमति स्वीकृत।

1. प्रतिवादी संख्या 4 संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत निगमित एक निगम है। यह पेरनॉर्ड रिकार्ड एस.ए. की एक अंतिम सहायक कंपनी है, जो दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के मादक पेय पदार्थों के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी

हुई है। इसका दावा है कि उसने वर्ष 1973 में अपने लाइसेंसधारी मेसर्स सीग्राम कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ट्रेडमार्क 'ब्लेंडर्स प्राइड' बनाया और अपनाया है। प्रतिवादी संख्या 4 के अनुसार, दुनिया भर में व्यापक बिक्री और विपणन के कारण, ट्रेडमार्क 'ब्लेंडर्स प्राइड' ने भारत सहित विभिन्न देशों में जबरदस्त प्रतिष्ठा हासिल की है। उक्त ट्रेडमार्क में अपने मालिकाना अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 4 ने 50 से अधिक देशों में उक्त ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया था और उसे पंजीकरण की अनुमति दी गई थी और वह अपने लाइसेंसधारी सीग्राम इंडिया प्राइवेट के माध्यम से भारत में 'ब्लेंडर्स प्राइड' व्हिस्की 1995 से बेच रहा है। इसने वर्ग 33 में दो आवेदनों के तहत ट्रेडमार्क 'ब्लेंडर्स प्राइड' के पंजीकरण के लिए भी आवेदन किया है, जिनका पंजीकरण लंबित है। समरूप ट्रेडमार्क 'ब्लेंडर्स प्राइड' के पंजीकरण के लिए अपीलकर्ता के आवेदन को ट्रेडमार्क जर्नल मेगा- 1 में विज्ञापित किया गया था। यह जर्नल 7 अक्टूबर, 2003 को प्रकाशित हुआ था। प्रतिवादी संख्या 4 ने 6.1.2004 को अपीलकर्ता के आवेदन के खिलाफ विरोध का नोटिस दाखिल करने के लिए एक महीने का समय बढ़ाने की मांग करते हुए फॉर्म टीएम-44 दाखिल किया था, यानी तीन महीने की वैधानिक अवधि के भीतर। 19.1.2004 को, प्रतिवादी संख्या 4 ने ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री, नई दिल्ली के समक्ष अपना विरोध नोटिस दायर किया था और इसे डीईएल-160325 के रूप में क्रमांकित किया गया था। 16.2.2004 को, ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री ने अपीलकर्ता को एक नोटिस जारी कर विरोध के उक्त नोटिस पर अपना प्रति कथन आमंत्रित किया था, और कहा था कि यदि प्रति कथन समय के भीतर दाखिल नहीं किया गया, तो ट्रेडमार्क आवेदन को छोड़ दिया गया माना जाएगा। हालाँकि, जब मामला इस प्रकार खड़ा हुआ, तो प्रतिवादी संख्या 4 को 20.1.2005 को पता चला कि अपीलकर्ता को 13.1.2004 को ही संख्या 618414 वाला एक ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था। हालाँकि, तुरंत,

अपने वकीलों के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 4 ने ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री को लंबित विपक्षी कार्यवाही के बारे में सूचित किया, जिनका निपटारा होना बाकी था।

2. चूंकि रजिस्ट्री से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जो रिट याचिका संख्या 2712 और 2713 /2005 थी। इस बीच, रजिस्ट्रार द्वारा 16.2.2005 को, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था अपीलकर्ता को ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 57(4) के तहत, जिसमें यह कहा गया था कि पंजीकरण प्रमाणपत्र गलत तरीके से जारी किया गया था, और चूंकि ट्रेडमार्क के रजिस्टर पर उक्त ट्रेडमार्क गलत तरीके से था, इसलिए धारा 57(4) के तहत रजिस्टर सुधारने का प्रस्ताव दिया गया था प्रतिवादी संख्या 4 के वकीलों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार।

3. इस बीच, ट्रेडमार्क को रजिस्टर से हटाने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर की गई रिट याचिका सुनवाई के लिए आई और दिनांक 2.3.2005 के एक आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ निपटा दी गई कि रजिस्ट्रार कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर यथाशीघ्र और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

4. इसके बाद, 14.3.2005 को, अपीलकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष एक विस्तृत उत्तर दायर किया गया, जिसमें उसने दलील दी कि कारण बताओ नोटिस स्वयं चलने योग्य नहीं था क्योंकि यह बॉम्बे के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया था, न कि नई दिल्ली द्वारा। इसके अलावा, यह कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 19.1.2004 को दायर किया गया विरोध स्पष्ट रूप से समय से परे था क्योंकि इसे प्रासंगिक तारीख से तीन महीने के भीतर दायर नहीं किया गया था, जो कि 6.1.2004 है, और उसके बाद यह दलील दी गई कि कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया जाए।

5. इस बीच, 14.1.2005 को इसके ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ता द्वारा जालंधर के जिला न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 के लाइसेंसधारी, सीग्राम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ। 21.4.2005 को, सीग्राम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक लिखित बयान दायर किया जिसमें उसने दलील दी कि वादी का पंजीकरण चुनौती के अधीन है और चूंकि सुधार की कार्यवाही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए मुकदमा उक्त सुधार कार्यवाही का अंतिम निस्तारण तक रोके जाने योग्य है। इसमें आगे दलील दी गई कि वादी (अर्थात् यहां अपीलकर्ता) द्वारा प्राप्त पंजीकरण शुरू से ही शून्य है और वादी को कोई अधिकार नहीं देता है और इसलिए, उल्लंघन के लिए मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया गया है।

6. जबकि मामला इस प्रकार था, अपीलकर्ता के उत्तर पर विचार करने के बाद, रजिस्ट्रार ने 26.5.2005 को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.2.2005 और अपीलकर्ता के उत्तर का उल्लेख किया और कहा कि विवादित चिह्न/असावधानी/त्रुटि से पंजीकृत किया गया था और ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 57(4) के तहत संदर्भित चिह्न को हटाकर रजिस्ट्रार को सुधारने का प्रस्ताव किया गया था। उसी पत्र द्वारा अपीलकर्ता को गलत तरीके से जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को तुरंत वापस करने का निर्देश दिया गया था, और आगे किसी भी उद्देश्य और किसी भी कार्यवाही में उपर्युक्त ट्रेडमार्क के संबंध में पंजीकरण के उक्त प्रमाण पत्र का उपयोग न करने का निर्देश दिया गया था।

7. उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा संख्या 10080-81 /2005 की एक रिट याचिका दायर की गई थी, और 31.5.2005 को उक्त आदेश के खिलाफ स्थगन का अंतरिम आदेश प्राप्त किया गया था। अंततः, 13.9.2005 को, दिल्ली उच्च

न्यायालय ने रजिस्ट्रार को 16.11.2005 को या उससे पहले उसके समक्ष कार्यवाही का निपटान करने का निर्देश दिया।

8. रजिस्ट्रार ने अपने आदेश दिनांक 14.11.2005 द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि उनके पास इस मामले में आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 125 के तहत, कार्यवाही केवल कानूनी तौर पर अपीलीय बोर्ड के समक्ष जारी रह सकती है और उसके नहीं।

9. अपीलीय बोर्ड के समक्ष दायर एक अपील में, अपीलीय बोर्ड ने अपने निर्णय दिनांक 6.10.2006 द्वारा, रजिस्ट्रार के आदेश को उलट दिया, और माना कि विरोध की नोटिस को रिकॉर्ड पर ले लिया गया था और क्रमांकित किया गया था, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर फॉर्म संख्या टीएम-44 समय विस्तार के लिए, को रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यह कि ऐसी स्वीकृति के बाद ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था अपीलकर्ता को, उनसे अपना प्रति-कथन दाखिल करने का आग्रह किया गया। ऐसा होने पर, ट्रेडमार्क का पंजीकरण 13.1.2004 को हुआ, अर्थात् विस्तारित एक महीने की समाप्ति से पहले ही, जाहिर तौर पर अधिनियम की धारा 23 के विपरीत है और इसलिए कानून में अमान्य होगा। गौरतलब है कि अपीलीय बोर्ड ने माना कि जब 16.2.2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, सीग्राम ने अभी तक अपना प्रति-कथन दायर नहीं किया था क्योंकि उसे मुकदमे के कागजात भी नहीं दिए गए थे, और चूंकि मुकदमा प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ दायर नहीं किया गया था लेकिन केवल सीग्राम के खिलाफ दायर किया गया था, धारा 125 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा और इसलिए रजिस्ट्रार के आदेश दिनांक 14.11.2005 को रद्द करना होगा। इसलिए, रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 21 के तहत विपक्षी कार्यवाही पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

10. अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या 16242/2006 के रूप में एक रिट याचिका दायर की गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 9.5.2008 द्वारा उपरोक्त अपीलीय बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया और रजिस्ट्रार द्वारा पारित दिनांक 14.11.2004 के आदेश को बरकरार रखा। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, अधिनियम की धारा 125 लागू होगी और इसलिए रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही पर रोक होगी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, इसलिए, व्हेलपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, मुंबई और अन्य, (1998) 8 एससीसी 1 में इस न्यायालय के फैसले के बाद, यह माना कि यह धारा लागू होगी क्योंकि उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी ने एक लिखित बयान दायर किया था ट्रेडमार्क की वैधता पर सवाल उठाने वाला और ऐसा होने पर, धारा 25(1) में गैर-अप्रत्याशित खंड रजिस्ट्रार के समक्ष अधिनियम की धारा 57 के तहत कार्यवाही पर रोक लगा देगा।

11. खंड पीठ के समक्ष एक अपील में, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 23(1) का उल्लंघन किया गया है, और धारा 125 इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगी क्योंकि रजिस्ट्रार की शुद्धता बनाए रखना रजिस्ट्रार का कर्तव्य है, जैसा कि हार्डी ट्रेडिंग लिमिटेड और अन्य बनाम एडिसन पेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड, (2003) 11 एससीसी 92 में माना गया है। आगे यह माना गया कि रजिस्ट्रार की शक्ति अधिनियम की धारा 57(4) के तहत अपनी गलतियों को सुधारना, धारा 125 में संदर्भित रजिस्ट्रार के सुधार के लिए आवेदन करने या न करने के पक्षों के अधिकार से पूरी तरह स्वतंत्र है। यदि धारा 125 को लागू किया जाना था इसका प्रभाव यह होगा कि यदि प्रतिवादी, उल्लंघन के मुकदमे में अमान्यता की दलील देने के बाद, अपीलीय बोर्ड के समक्ष सुधार दाखिल करने के साथ आगे नहीं बढ़ने का विकल्प चुनता है, तो रजिस्ट्रार द्वारा की गई त्रुटि रजिस्ट्रार पर बनी रह सकती

है। ऐसी स्थिति में रजिस्टर की शुद्धता को कायम नहीं रखा जा सकेगा, एक ऐसा परिणाम जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी यदि धारा 125 की सही व्याख्या की जाती है। आखिरकार खंड पीठ ने माना कि 13.1.2004 को पंजीकरण प्रदान करना अधिनियम की धारा 23(1) के विपरीत होने के कारण स्वयं अमान्य था। अंततः, निम्नलिखित शर्तों पर अपील की अनुमति दी गई:

"अधिनियम की धारा 23(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विरोध दर्ज कराने की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद ही पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। अपीलकर्ता ने चौथे प्रतिवादी के ट्रेडमार्क के पंजीकरण के विरोध में समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया था और विरोध के नोटिस को रजिस्ट्रार द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया था। उपरोक्त तथ्य दिनांक 16 फरवरी, 2004 के कारण बताओ आदेश और 26 मई, 2005 के अंतरिम आदेश से स्पष्ट है। ऐसे आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता कि विरोध दर्ज करने का समय समाप्त हो गया था। पूरे मुद्दे पर अपीलीय बोर्ड द्वारा विचार किया गया था जो अधिनियम की धारा 2 (जेडई) के अनुसार एक न्यायाधिकरण है। न्यायाधिकरण अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि पंजीकरण उल्लंघन में था अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और रजिस्ट्रार को चौथे प्रतिवादी के आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

उपरोक्त तथ्यों और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद हम मानते हैं कि अपीलीय बोर्ड द्वारा मामले की नए सिरे से सुनवाई का निर्देश देकर कोई अन्याय नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।" [अनुच्छेद 22 और 23 पर]

12. श्रीमती प्रथिबा सिंह अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनिवार्य रूप से तर्क दिया कि यद्यपि एक महीने की समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले दायर किया गया था, फिर भी रजिस्ट्रार ने देरी को माफ करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया था। स्पष्ट है कि विरोध दाखिल करने की अवधि 6.1.2004 को समाप्त हो गई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 21 रजिस्ट्रार को निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन को "अनुमति" देने की बात करती है, और इसलिए धारा 21(1) में "अनुमति" अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट हो जाएगा कि रजिस्ट्रार द्वारा एक लिखित आदेश होना चाहिए और इसलिए अनुभाग द्वारा विस्तार देने वाले किसी निहित आदेश पर विचार नहीं किया गया है। अतः 13.1.2004 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र कानून के अनुरूप था। इसके अलावा, चूंकि कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.2.2005 को बॉम्बे से जारी किया गया था, यह स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना था। इसलिए, पंजीकरण की अमान्यता की दलील देते हुए अपीलकर्ता के लाइसेंसधारी द्वारा दायर उल्लंघन के मुकदमे में एक लिखित बयान दायर किए जाने के मद्देनजर, धारा 125 सभी चारों पर लागू होती है और व्हेलपूल कॉरपोरेशन (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय रजिस्ट्रार नॉन एस्ट के समक्ष सुधार कार्यवाही प्रस्तुत करने के लिए लागू होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तथ्य यह है कि ऑस्टिन निकोल्स उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी नहीं है, इससे इसके लाइसेंसधारी के रूप में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीग्राम एक प्रतिवादी है और उसने पंजीकृत ट्रेडमार्क की अमान्यता के बारे में एक याचिका दायर की है। सीग्राम केवल ऑस्टिन निकोल्स के अधिकारों को लागू कर रहा है और दोनों पक्षों का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एक ही है। इस प्रकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उल्लंघनकारी मुकदमे में प्रतिवादी ऑस्टिन निकोल्स नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 57(4) के तहत रजिस्ट्रार की स्वतः प्रेरणा शक्तियां अधिनियम

की धारा 125(1) द्वारा छीन ली गई हैं, क्योंकि गैर-अप्रत्याशित खंड संपूर्ण धारा 57 को कवर करता है। जहां विधायिका का इरादा है केवल एक उपधारा निर्दिष्ट करें, इसने उस आशय को स्पष्ट भाषा में ज़ाहिर कर दिया है। उस उद्देश्य के लिए, उन्होंने व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 107(1) का हवाला दिया जो संपूर्ण धारा 46, संपूर्ण धारा 56 और केवल धारा 47 उप-धारा (4) को संदर्भित करता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि वास्तव में, हालांकि इसे धारा 57(4) के तहत ऑस्टिन निकोल्स के आदेश पर की गई कार्यवाही के रूप में देखा गया है, वास्तव में यह ऐसी कोई कार्यवाही नहीं थी। उन्होंने रजिस्ट्रार के आदेश दिनांक 14.11.2005 के साथ-साथ एकल न्यायाधीश के दिनांक 9.5.2008 के फैसले का प्रचुरता से उल्लेख किया और कहा कि चूंकि कारण बताओ नोटिस स्वयं अधिकार क्षेत्र के बिना था, इसलिए ये आदेश सही थे और इन्हें बहाल किया जाना चाहिए।

13. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुधीर चंद्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने हमारे सामने तर्क दिया कि जब रजिस्ट्रार ने अधिनियम की धारा 21(2) के तहत दिनांक 16.2.2004 को पत्र जारी किया और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर विरोध के नोटिस पर अपीलकर्ता से उक्त धारा के तहत प्रति-कथन मांगा, यह स्पष्ट था कि समय के भीतर लागू समय के विस्तार की अनुमति दी गई थी। उन्होंने विशेष रूप से अधिनियम की धारा 131 का उल्लेख किया और कहा कि रजिस्ट्रार को संतुष्ट होना चाहिए कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण हैं और यदि वह इतना संतुष्ट है, तो उसे समय विस्तार के लिए आवेदन का निपटान करने से पहले पक्षों को सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 उल्लंघन के मुकदमे में एक पक्ष नहीं था, इसलिए धारा 125 का इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। उन्होंने

आगे तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 57(4) के तहत रजिस्ट्रार की स्वतः प्रेरणा शक्तियों को अधिनियम की धारा 125 द्वारा छीना नहीं गया है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 125 का संबंध "रजिस्टर के सुधार के लिए एक आवेदन" से है। उन्होंने हमें धारा 2(जेड ई) के तहत "न्यायाधिकरण " की परिभाषा के बारे में बताया और कहा कि जहां रजिस्ट्रार के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है, यह अधिनियम के तहत सभी उद्देश्यों के लिए आवश्यक रूप से एक "न्यायाधिकरण " होगा। उन्होंने तर्क दिया कि हार्डी के मामले (उपरोक्त) में फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से संदर्भित किया गया था और उस पर भरोसा किया गया था और अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को एक स्वतंत्र कर्तव्य के रूप में रजिस्टर की शुद्धता बनाए रखनी होगी। उनके अनुसार, व्हेलपूल के मामले में निर्णय वास्तव में उनके मुवक्किल के मामले का समर्थन करता था, और किसी भी मामले में, तथ्यों पर, यह स्पष्ट था कि वर्तमान मामले के तथ्यों के विपरीत, धारा 125 लागू होती।

14. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। मामले के गुण दोष पर चर्चा शुरू करने से पहले, ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 में निहित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है:-

"धारा 2- परिभाषाएँ और व्याख्या

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (जेडई) "न्यायाधिकरण " का अर्थ रजिस्ट्रार या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय बोर्ड है, जिसके समक्ष संबंधित कार्यवाही लंबित है;

धारा 21-पंजीकरण का विरोध

(1) कोई भी व्यक्ति, पंजीकरण के लिए किसी आवेदन के विज्ञापन या पुनः विज्ञापन की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो

कुल मिलाकर एक महीने से अधिक नहीं होगी, रजिस्ट्रार, निर्धारित तरीके से और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, उसे किए गए आवेदन पर कर सकता है, पंजीकरण के विरोध में रजिस्ट्रार को निर्धारित तरीके से लिखित में नोटिस देने की अनुमति देता है।

(2) रजिस्ट्रार पंजीकरण के लिए आवेदक को नोटिस की एक प्रति भेजेगा और विरोध के नोटिस की ऐसी प्रति आवेदक द्वारा प्राप्त होने के दो महीने के भीतर, आवेदक निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार को एक प्रति-कथन भेजेगा उन आधारों के विवरण का जिन पर वह अपने आवेदन के लिए भरोसा करता है, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपना आवेदन छोड़ दिया है।

(3) यदि आवेदक ऐसा प्रति-कथन भेजता है, तो रजिस्ट्रार विरोध की नोटिस देने वाले व्यक्ति को उसकी एक प्रति देगा।

(4) कोई भी साक्ष्य जिस पर प्रतिद्वंद्वी और आवेदक भरोसा कर सकते हैं, निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि वे चाहें तो रजिस्ट्रार उन्हें सुनवाई का अवसर देगा।

(5) रजिस्ट्रार, पक्षों को सुनने के बाद, यदि आवश्यक हो, और साक्ष्य पर विचार करते हुए, यह निर्णय लेगा कि क्या और किन शर्तों या सीमाओं के अधीन, यदि कोई हो, पंजीकरण की अनुमति दी जानी है, और आपत्ति के आधार पर विचार कर सकता है चाहे प्रतिद्वंद्वी द्वारा निर्भर किया गया है या नहीं।

(6) जहां विरोध की नोटिस देने वाला व्यक्ति या ऐसे नोटिस की एक प्रति प्राप्त होने के बाद प्रति-कथन भेजने वाला आवेदक न तो भारत में रहता है और न ही व्यापार करता है, रजिस्ट्रार उससे अपने समक्ष कार्यवाही की लागतों के लिए सुरक्षा देने की मांग कर सकता है और ऐसी सुरक्षा विधिवत न दिए जाने पर, जैसा भी मामला हो, विरोध या आवेदन को त्याग दिया हुआ माना जा सकता है।

(7) रजिस्ट्रार, अनुरोध पर, विरोध की नोटिस या किसी प्रति-कथन में किसी भी त्रुटि को सुधारने या किसी भी संशोधन की अनुमति ऐसी शर्तों पर दे सकता है, जैसा वह उचित समझता है।

धारा 23-पंजीकरण

(1) धारा 19 के प्रावधानों के अधीन, जब रजिस्ट्रार के भाग ए या भाग बी में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए एक आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और या तो-

(ए) आवेदन का विरोध नहीं किया गया है और विरोध की नोटिस का समय समाप्त हो गया है; या

(बी) आवेदन का विरोध किया गया है और आवेदक के पक्ष में विरोध का फैसला किया गया है,

रजिस्ट्रार, जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे, उक्त व्यापार चिह्न को रजिस्ट्रार के भाग ए या भाग बी में, जैसा भी मामला हो, पंजीकृत करेगा, और पंजीकृत होने पर व्यापार चिह्न को बनने की तारीख के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा। उक्त आवेदन और तारीख, धारा 131 के प्रावधानों के अधीन, पंजीकरण की तारीख मानी जाएगी।

(2) ट्रेड मार्क के पंजीकरण पर, रजिस्ट्रार आवेदक को उसके पंजीकरण के निर्धारित फॉर्म में ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री की मुहर के साथ सीलबंद एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) जहां आवेदक की ओर से चूक के कारण आवेदन की तारीख से बारह महीने के भीतर व्यापार चिह्न का पंजीकरण पूरा नहीं होता है, रजिस्ट्रार निर्धारित तरीके से आवेदक को नोटिस देने के बाद, आवेदन को तब तक परित्यक्त मान सकता है जब तक कि वह नोटिस में उस ओर से निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा न हो जाए।

(4) रजिस्ट्रार किसी लिपिकीय त्रुटि या स्पष्ट गलती को सुधारने के उद्देश्य से रजिस्टर या पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन कर सकता है।

57. पंजीकरण रद्द करने या परिवर्तन करने और रजिस्टर को सुधारने की शक्ति.-

(1) किसी भी व्यथित व्यक्ति द्वारा अपीलीय बोर्ड या रजिस्ट्रार को निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर, न्यायाधिकरण ऐसा आदेश दे सकता है जो वह किसी उल्लंघन के आधार पर व्यापार चिह्न के पंजीकरण को रद्द करने या बदलने के लिए उचित समझे, या उसके संबंध में रजिस्टर पर दर्ज किसी शर्त का पालन करने में विफलता पर।

(2) अनुपस्थिति या लोप से व्यथित कोई भी व्यक्ति रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि के लिए, या पर्याप्त कारण के बिना रजिस्टर में की गई किसी भी प्रविष्टि के लिए, या रजिस्टर में गलत तरीके से दर्ज की गई किसी भी प्रविष्टि के लिए, या रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि में कोई त्रुटि या दोष होने पर, अपीलीय बोर्ड में निर्धारित तरीके से आवेदन किया जा सकता है। या रजिस्ट्रार को, और न्यायाधिकरण प्रविष्टि बनाने, हटाने या बदलने के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(3) न्यायाधिकरण इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही में किसी भी प्रश्न पर निर्णय ले सकता है जो रजिस्टर के सुधार के संबंध में निर्णय लेने के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकता है।

(4) अधिकरण, अपने स्वयं के प्रस्ताव से, संबंधित पक्षों को निर्धारित तरीके से नोटिस देने और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद, उप-धारा (1) या उप-धारा(2) में निर्दिष्ट कोई भी आदेश दे सकता है।

(5) रजिस्टर में सुधार करने वाले अपीलीय बोर्ड के किसी भी आदेश में निर्देश दिया जाएगा कि सुधार की नोटिस रजिस्ट्रार को निर्धारित तरीके से दी जाएगी, जो ऐसी नोटिस प्राप्त होने पर तदनुसार रजिस्टर को सुधारेगा।

धारा 124-कार्यवाहियों पर रोक जहां व्यापार चिह्नों के पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाया जाता है, आदि।

(1) जहां व्यापार चिह्न के उल्लंघन के किसी मुकदमे में-

(ए) प्रतिवादी का कहना है कि वादी के व्यापार चिह्न का पंजीकरण अमान्य है;

या

(बी) प्रतिवादी धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ई) के तहत बचाव करता है और वादी प्रतिवादी के व्यापार चिह्न के पंजीकरण की अमान्यता का अनुरोध करता है,

मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायालय (जिसे इसके बाद न्यायालय कहा गया है),-

(i) यदि वादी या प्रतिवादी के व्यापार चिह्न के संबंध में रजिस्टर के सुधार के लिए कोई कार्यवाही रजिस्ट्रार या अपीलीय बोर्ड के समक्ष लंबित है, तो ऐसी कार्यवाही के अंतिम निपटान तक मुकदमे पर रोक लगाएं;

(ii) यदि ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और अदालत संतुष्ट है कि वादी या प्रतिवादी के व्यापार चिह्न के पंजीकरण की अमान्यता के बारे में याचिका प्रथम दृष्टया तर्कसंगत है, तो उसी के संबंध में एक मुद्दा उठाएं और मामले को कुछ अवधि के लिए स्थगित कर दें संबंधित पक्ष को रजिस्टर में सुधार के लिए अपीलीय बोर्ड में आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए मुद्दे की रूपरेखा तैयार होने की तारीख से तीन महीने।

(2) यदि संबंधित पक्ष अदालत में यह साबित कर देता है कि उसने उप-धारा (1) के खंड (बी) (ii) में निर्दिष्ट कोई भी ऐसा आवेदन उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर या

अदालत द्वारा दिए गए विस्तारित समय के भीतर किया है। पर्याप्त कारण के लिए अनुमति दी जा सकती है, सुधार की कार्यवाही के अंतिम निपटान तक मुकदमे की सुनवाई रोक दी जाएगी।

(3) यदि उपर्युक्त जैसा कोई आवेदन निर्दिष्ट समय के भीतर या अदालत द्वारा अनुमति दिए गए विस्तारित समय के भीतर नहीं किया गया है, तो संबंधित व्यापार चिह्न के पंजीकरण की वैधता के मुद्दे को छोड़ दिया गया माना जाएगा और अदालत मामले के अन्य मुद्दों के संबंध में मुकदमे पर आगे बढ़ेगी।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी सुधार कार्यवाही में दिया गया अंतिम आदेश पक्षों पर बाध्यकारी होगा और अदालत ऐसे आदेश के अनुरूप मुकदमे का निपटारा करेगी जहां तक यह ट्रेड मार्क के पंजीकरण की वैधता के मुद्दे से संबंधित है।

(5) इस धारा के तहत व्यापार चिह्न के उल्लंघन के मुकदमे पर रोक अदालत को कोई भी अंतरिम आदेश देने से नहीं रोकेंगी (जिसमें कोई भी निषेधाज्ञा देने वाला आदेश जिसमें खाता रखने, रिसीवर नियुक्त करने या किसी संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया गया हो) शामिल है। मुकदमे पर रोक की अवधि के दौरान।

धारा 125-कुछ मामलों में रजिस्टर में सुधार के लिए अपीलीय बोर्ड को आवेदन किया जाना

(1) जहां किसी पंजीकृत व्यापार चिह्न के उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा वादी के व्यापार चिह्न के पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाया जाता है या जहां ऐसे किसी मुकदमे में प्रतिवादी उप-धारा के खंड (ई) के तहत बचाव करता है (2) धारा 30 और वादी प्रतिवादी के व्यापार चिह्न के पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाता है, संबंधित व्यापार चिह्न के पंजीकरण की वैधता का मुद्दा केवल रजिस्टर के सुधार के लिए

एक आवेदन पर निर्धारित किया जाएगा और, इसके बावजूद धारा 47 या धारा 57 में कुछ भी निहित है, ऐसा आवेदन अपीलीय बोर्ड को किया जाएगा न कि रजिस्ट्रार को।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन, जहां धारा 47 या धारा 57 के तहत रजिस्ट्रार को रजिस्टर में सुधार के लिए आवेदन किया जाता है, रजिस्ट्रार, यदि वह उचित समझे, किसी भी स्तर पर आवेदन को संदर्भित कर सकता है। अपीलीय बोर्ड को कार्यवाही की जानकारी।

धारा 131-समय का विस्तार

(1) यदि रजिस्ट्रार निर्धारित तरीके से और निर्धारित शुल्क के साथ दिए गए आवेदन पर संतुष्ट है कि किसी भी कार्य को करने के लिए समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण है (इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया समय नहीं है), चाहे इस प्रकार निर्दिष्ट समय समाप्त हो गया हो या नहीं, वह ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह लगाना उचित समझे, समय बढ़ा सकता है और पक्षों को तदनुसार सूचित कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा कि रजिस्ट्रार को समय विस्तार के लिए किसी आवेदन का निपटान करने से पहले पक्षों को सुनने की आवश्यकता है, और इस धारा के तहत रजिस्ट्रार के किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी।

15. इस मामले में ध्यान देने वाली पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने धारा 21(2) के तहत उसे दी गई तीन महीने की अवधि के भीतर विरोध का नोटिस दाखिल करने के लिए एक महीने का समय बढ़ाने की मांग की और निर्धारित समय में ऐसा किया। वैधानिक फॉर्म टीएम-44 में कहा गया है कि विस्तार का कारण यह होगा कि उन्हें विरोध का नोटिस दाखिल करने से पहले कानूनी सलाह

लेनी होगी। नोटिस करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विरोध का नोटिस दिनांक 19.1.2004 एक महीने की विस्तारित अवधि के भीतर बनाया गया था, और रजिस्ट्रार द्वारा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर लिया गया था, जैसा कि रजिस्ट्रार के पत्र दिनांक 16.2.2004 में दर्शाया गया है। चूँकि यह पत्र इस मामले का निर्णय लेने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है:-

"पंजीकृत पोस्ट ए.डी.

क्रमांक टीओपी/ दिनांक: 16-फ़रवरी-2004

प्रेषक: ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार,

सेवा में,

मैसर्स एसीएमई कंपनी

दिल्ली-110001

विषय: जगजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर वर्ग 33 में आवेदन संख्या 618414 का विरोध संख्या 160325

श्रीमान/महोदय/मैडम,

ट्रेड एंड मर्चेन्डाइज मार्क्स एक्ट, 1999 की धारा 21(2) के अनुसरण में, ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित आवेदन पर दायर विरोध की नोटिस की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश दिया गया है।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ अधिनियम और व्यापार एवं व्यापारिक चिह्न नियम, 2002 की धारा 21(2) और नियम 48 की ओर जिस में कहा गया है कि जिन आधारों पर आप/आवेदक अपने आवेदन के लिए भरोसा करते हैं, उनका प्रतिकथन इस कार्यालय में फॉर्म टीएम-6 पर तीन प्रतियों में दाखिल

किया जाना चाहिए विरोध के नोटिस की प्रति आपको प्राप्त होने के दो महीने के भीतर। प्रतिकथन में यह भी बताया जाना चाहिए कि विपक्ष के नोटिस में कथित कोई भी तथ्य आपके/आवेदकों द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

मुझे आपको यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि यदि उपरोक्त समय के भीतर इस रजिस्ट्री में ऐसा कोई प्रतिवाद प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आवेदकों ने आपका आवेदन त्याग दिया है (व्यापार और व्यापारिक वस्तु चिह्न अधिनियम की धारा 21(2) के तहत, 1999)।

आपका विश्वासी,

व्यापार चिह्नों के सहायक परीक्षक

दिनांक: 16-फरवरी-2004

क्रमांक टीओपी/

प्रतिलिपि आरईएमएफआरवाय एवं एसजीएआर को नोटिस हेतु अग्रेषित की गई।

एसडी/-

व्यापार चिह्नों के सहायक परीक्षक

दिनांक: 16-फरवरी.2004"

16. इस पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि विरोध की नोटिस को रिकार्ड में ले लिया गया था। ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि एक महीने का समय नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि विरोध का उक्त नोटिस केवल 19.1.2004 को दायर किया गया था, यानी 6.1.2004 को तीन महीने खत्म होने के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर। हालाँकि अधिनियम की धारा 131 रजिस्ट्रार की संतुष्टि को संदर्भित करती है

और उन शर्तों को संदर्भित करती है जिन्हें वह लागू करना उचित समझ सकता है, यह स्पष्ट है कि यदि वह समय बढ़ाना चाहता है तो उसे हर मामले में एक अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। मैसर्स एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई बनाम बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, चेन्नई और अन्य, एआईआर 2009 जी मद्रास 196 के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को, विशेष रूप से उसके अनुच्छेद 27 में, उस धारा 131 को दिखाने के लिए संदर्भित किया गया था कि इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि उक्त उपधारा वहां लागू नहीं होगी जहां इस अधिनियम में किसी कार्य को करने का समय स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। यह सच है कि विरोध का नोटिस दाखिल करने का समय धारा 21(1) में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए समय के भीतर किया जाना है और इसलिए अधिनियम की धारा 131 लागू नहीं होगी। हालाँकि, धारा 131 एक इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि रजिस्ट्रार द्वारा समय का विस्तार एक मंत्रिस्तरीय कार्य है जिसके लिए किसी सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

17. श्रीमती प्रथिबा सिंह ने यह भी तर्क दिया कि धारा 21(1) में अभिव्यक्ति "अनुमति" आगे दिखाएगी कि समय विस्तार देने के लिए लिखित रूप में एक आदेश होना चाहिए और वर्तमान मामले में ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने एम. मजहरुद्दीन अली बनाम सरकार एपी, (2000) 10 एससीसी 383, का भी हवाला दिया अनुच्छेद 7 और 11 पर, यह दिखाने के लिए कि अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों में छूट के संदर्भ में, एक लिखित आदेश द्वारा एक विशिष्ट छूट आवश्यक है अन्यथा यह कहा जा सकता है कि कानून में ऐसे नियमों की कोई छूट नहीं है। हम ध्यान दें कि उपरोक्त निर्णय संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल लिखित रूप में और उक्त अनुच्छेद द्वारा निर्धारित तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्यपाल की

शक्ति एक कार्यकारी शक्ति है न कि अर्ध-न्यायिक, जैसा कि वर्तमान मामले में रजिस्ट्रार की शक्ति है। इसलिए, यह निर्णय अपीलकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। इसके अलावा, यह स्थापित कानून है कि प्रक्रियात्मक प्रावधानों को इस तरह से समझा जाना चाहिए जो न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है और नष्ट नहीं करता है। इस न्यायालय ने कैलाश बनाम नन्हक्, (2005) 4 एससीसी 480 में अनुच्छेद 28 और 29 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

"प्रक्रिया के सभी नियम न्याय के दास हैं। प्रक्रियात्मक कानून के ड्राफ्ट्समैन द्वारा प्रयुक्त भाषा उदार या कठोर हो सकती है, लेकिन तथ्य यह है कि प्रक्रिया निर्धारित करने का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। एक प्रतिकूल प्रणाली में, आम तौर पर किसी भी पक्ष को न्याय वितरण की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जब तक कानून की स्पष्ट और विशिष्ट भाषा द्वारा मजबूर न किया जाए, सीपीसी या किसी अन्य प्रक्रियात्मक अधिनियम के प्रावधानों को इस तरह से नहीं समझा जाना चाहिए जिससे अदालत न्याय के अंत में असाधारण परिस्थितियों का सामना करने में असहाय रह जाए। सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य [(1975) 1 एससीसी 774] में कृष्णा लायर, न्यायाधिपति द्वारा की गई टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं: (एससीसी पृष्ठ 777, अनुच्छेद 5-6)

"कानून के हार्थों न्याय की नश्वरता एक न्यायाधीश की अंतरात्मा को परेशान करती है और कानून सुधारक पर क्रोधपूर्ण पूछताछ का संकेत देती है।

प्रक्रियात्मक कानून कुछ प्रणालियों पर इतना हावी है कि मौलिक अधिकारों और पर्याप्त न्याय पर हावी होता है। मानवतावादी नियम है कि प्रक्रिया दासी होनी चाहिए, मालकिन नहीं कानूनी न्याय की जो एक अवशिष्ट शक्ति को निहित करने पर विचार करने के लिए बाध्य करता है न्यायाधीशों में पूर्व डेबिटो जस्टिटिया का कार्य करने के

लिए जहां दुखद अगली कड़ी अन्यथा पूरी तरह से असमान होगी...न्याय न्यायशास्त्र प्रक्रिया का लक्ष्य है, उतना ही वास्तविक भी।"

पंजाब राज्य बनाम शामलाल मुरारी [(1976) 1 एससीसी 719 1976 एससीसी (एल एंड एस) 118] में न्यायालय ने इस सिद्धांत पर अनिवार्य मानी जाने वाली संपूर्ण दिशाओं में संतुलन के दृष्टिकोण को स्पष्ट शब्दों में मंजूरी दे दी: (एससीसी पी। 720)

"प्रक्रियात्मक कानून अत्याचारी नहीं बल्कि सेवक है, बाधा नहीं है बल्कि न्याय में सहायता है। प्रक्रियात्मक नुस्खे दासी हैं न कि स्वामिनी, स्नेहक हैं, न्याय के प्रशासन में प्रतिरोधी नहीं।"

घनश्याम दास बनाम डोमिनियन ऑफ इंडिया [(1984) 3 एससीसी 461 में न्यायालय ने केवल प्रक्रिया से संबंधित विशेषण कानून के एक हिस्से की व्याख्या इस तरह से करने की आवश्यकता को दोहराया ताकि न्याय के उद्देश्य को पराजित करने के बजाय उसे आगे बढ़ाया जा सके। चूंकि प्रक्रिया के सभी नियम इसी सिद्धांत पर आधारित हैं।" (अनुच्छेद 28 और 29 पर)

18. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार द्वारा समय बढ़ाया गया है, जैसा कि दिनांक 16.2.2004 के पत्र से प्रमाणित है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 6.1.2004 से 30 दिनों की विस्तारित अवधि से पहले दिया गया कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 23(1) का उल्लंघन होगा। मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलीय बोर्ड और खंड पीठ यह घोषित करने में स्पष्ट रूप से सही हैं कि पंजीकरण प्रमाणपत्र, 13.1.2004 को जारी किया गया, धारा 23(1)(ए) का उल्लंघन होगा, और रजिस्टर उक्त ट्रेडमार्क को वहां से हटाकर ठीक किया जाएगा।

19. हम श्रीमती प्रथिबा सिंह द्वारा दिए गए तर्क का निपटारा कर सकते हैं कि अधिनियम की धारा 57(4) के तहत दिनांक 16.2.2005 का कारण बताओ नोटिस

अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि यह बॉम्बे में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया था, न कि दिल्ली में अधिकारियों द्वारा। चूंकि ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन दिल्ली में किया गया था, और उसके बाद की सभी कार्यवाही दिल्ली में हुई, इसलिए यह कारण बताओ नोटिस भी दिल्ली में ही जारी किया जाना चाहिए था।

20. हम देख सकते हैं कि अधिनियम की धारा 57(4) के तहत स्व-प्रेरक शक्ति का प्रयोग केवल रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जा सकता है उक्त धारा की उपधारा (1) और (2) में उल्लेखित "न्यायाधिकरण" होने के नाते। ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 3 उपयुक्त है। धारा 3 बताती है: "धारा 3- रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति-

(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिनोटिस द्वारा, एक व्यक्ति को पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेड मार्क्स के महानियंत्रक के रूप में नियुक्त कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ट्रेड मार्क्स का रजिस्ट्रार होगा।

(2) केंद्र सरकार ऐसे अधिकारियों को ऐसे पदनामों के साथ नियुक्त कर सकती है, जैसा निर्वाहन के लिए उचित समझती है रजिस्ट्रार के पर्यवेक्षण और निर्देशन के तहत, इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के ऐसे कार्यों के लिए जिन्हें वह समय-समय पर अधिकृत कर सकता है, निर्वाहन के लिए।"

21. इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा 57(4) के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग केवल ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसा केवल एक रजिस्ट्रार है- और उसका पंजीकृत कार्यालय बंबई में है। दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में सहायक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार, बॉम्बे के अधीक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करते हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 3(2) से स्पष्ट है। इसलिए, यह बिंदु D निरर्थक है।

22. अब हम दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए एक महत्वपूर्ण तर्क पर आते हैं: अधिनियम की धारा 125 की सही व्याख्या। अधिनियम की धारा 124 में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि जहां, ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मुकदमे में, प्रतिवादी दलील देता है कि वादी के ट्रेडमार्क का पंजीकरण अमान्य है, तो मुकदमे की सुनवाई करने वाली अदालत सुधार कार्यवाही के अंतिम निपटान तक मुकदमे पर रोक लगाएगी। जैसा भी मामला हो, रजिस्ट्रार या अपीलीय बोर्ड के समक्ष।

23. धारा 124 के तहत योजना धारा 125 के दायरे को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि जहां उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर करने से पहले रजिस्टर के सुधार की कार्यवाही लंबित है जिसमें प्रतिवादी दलील देता है कि पंजीकरण का पंजीकरण वादी का ट्रेडमार्क अमान्य है, ऐसी कार्यवाही अधिनियम की धारा 57(1) और (2) के मद्देनजर या तो रजिस्ट्रार के समक्ष या अपीलीय बोर्ड के समक्ष की जा सकती है। लेकिन, यदि उल्लंघन के लिए ऐसे मुकदमे दायर करने के बाद सुधार की कार्यवाही शुरू की जानी है जिसमें प्रतिवादी यह दलील देता है कि वादी के ट्रेडमार्क का पंजीकरण अमान्य है, तो सुधार की कार्यवाही केवल अपीलीय बोर्ड के समक्ष ही की जा सकती है, रजिस्ट्रार के समक्ष नहीं।

24. यह देखा जाएगा कि धारा 124(1) केवल उल्लंघन के मुकदमे के वादी और प्रतिवादी को संदर्भित करती है, और धारा 124(1)(ii) विशेष रूप से संबंधित पक्ष" को संदर्भित करता है जो रजिस्टर के सुधार के लिए अपीलीय बोर्ड को आवेदन करेगा। इसी प्रकार, धारा 125 भी पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मुकदमे में केवल "वादी" और "प्रतिवादी" को संदर्भित करती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि रजिस्टर में सुधार के लिए आवेदन या तो प्रतिवादी द्वारा किया जा सकता है जो मुकदमे में दलील देता है कि वादी के ट्रेडमार्क का पंजीकरण अमान्य है, या वादी द्वारा जो पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का ट्रेडमार्क जहां प्रतिवादी धारा 30(2)(ई) के तहत

बचाव करता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा 125(1) में निर्दिष्ट रजिस्टर के सुधार के लिए आवेदन केवल उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन (वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए) हो सकता है। प्रतिवादी सीग्राम है न कि ऑस्टिन निकोल्स, यह स्पष्ट है कि धारा का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। श्रीमती प्रथिबा सिंह ने निवेदन किया कि सीग्राम केवल ऑस्टिन निकोल्स का लाइसेंसधारी है और दोनों पक्षों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एक ही हैं, इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि ऑस्टिन निकोल्स को यहां अपीलकर्ता के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा गया है। सीग्राम फिर से दो अलग-अलग कंपनियां बन गईं- सीग्राम मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और सीग्राम डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड। वादी का आरोप है कि उपरोक्त दोनों कंपनियां शराब के निर्माण और वितरण में लगी हुई हैं और ट्रेडमार्क "ब्लैंडर्स प्राइड" के तहत मादक पेय बेचती और निर्यात करती हैं, जो वादी का पंजीकृत ट्रेडमार्क है। वाद में यह नहीं बताया गया है कि पहला और दूसरा प्रतिवादी ऑस्टिन निकोल्स के उक्त ट्रेडमार्क के लाइसेंसधारी हैं। वास्तव में, वाद के अनुच्छेद 10 में, वादी द्वारा एक विशिष्ट कथन है कि आवश्यक पूछताछ करने पर, वादी को पता चला है कि प्रतिवादियों ने अपने पक्ष में ट्रेडमार्क 'ब्लैंडर्स प्राइड' के पंजीकरण के लिए आवेदन भी नहीं किया है। यह भी देखा जा सकता है कि यह मुकदमा उल्लंघन के साथ-साथ पारित करने का भी मुकदमा है, और यह महत्वपूर्ण है कि ऑस्टिन निकोल्स को उक्त मुकदमे में प्रतिवादी पक्ष नहीं बनाया गया है। साथ ही, संबंधित ट्रेडमार्क के पंजीकरण की वैधता के मुद्दे को रजिस्टर के सुधार के लिए आवेदन में निर्धारित किया जाना है, जो स्पष्ट रूप से केवल मुकदमे के पक्षों को बाध्य करेगा और किसी को नहीं। इन कारणों से, सुधार के लिए आवेदन, उक्त मुकदमे में किसी भी पक्ष प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन के लिए और पारित करने के लिए नहीं किया गया है, धारा 125(1) का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

25. दूसरे, हाई कोर्ट की खण्ड पीठ भी सही है इस तर्क में कि धारा 125(1) केवल रजिस्टर के सुधार के आवेदनों पर लागू होगी न कि धारा 57(4) के तहत रजिस्ट्रार की स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग के लिए। कारण खोजना कठिन नहीं है। यदि रजिस्ट्रार को रजिस्टर की शुद्धता बनाए रखने के लिए धारा 57(4) के तहत स्वतः संज्ञान लेने से रोक दिया गया है, तो ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहां प्रतिवादी, उल्लंघन के मुकदमे में अमान्यता की दलील देने के बाद, आगे नहीं बढ़ने का विकल्प चुनता है अपीलीय बोर्ड के समक्ष सुधार याचिका दाखिल करने के साथ। यह विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है: उदाहरण के लिए, उस मामले को लें, जहां उल्लंघन के मुकदमे में अमान्यता की दलील देने के बाद, मामले में समझौता हो जाता है और प्रतिवादी अपीलीय बोर्ड के समक्ष सुधार याचिका दायर नहीं करता है। ट्रेडमार्क के रजिस्टर की शुद्धता बनाए रखने की रजिस्ट्रार की शक्ति ऐसे मामलों में भी बरकरार रहेगी, जैसा कि हार्डी के मामले में फैसले से माना गया है। इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में, "व्यथित व्यक्ति" के अर्थ की ओर ध्यान दिलाते हुए इस प्रकार कहा:-

"पीड़ित व्यक्ति" वाक्यांश एक वैध शिकायत या अपील के लिए एक सामान्य वैधानिक पूर्व शर्त है। जिस संदर्भ में यह घटित होता है, उसके आधार पर इस वाक्यांश का अलग-अलग अर्थ लगाया गया है। अधिनियम के तीन खंड अर्थात् धारा 46, 56 और 69 में शामिल हैं वाक्यांश। धारा 46 गैर-उपयोग के आधार पर रजिस्टर से एक पंजीकृत ट्रेडमार्क को हटाने से संबंधित है। यह धारा मानती है कि जो पंजीकरण वैध रूप से किया गया था, उसे बाद के गैर-उपयोगकर्ता द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरी ओर धारा 56 हाथ उन स्थितियों से निपटता है जहां प्रारंभिक पंजीकरण नहीं होना चाहिए था या गलत तरीके से किया गया था। इस अनुभाग में शामिल स्थितियों में शामिल हैं:- (ए) पंजीकरण के लिए एक शर्त का उल्लंघन या पालन करने में विफलता; (बी) एक प्रविष्टि की अनुपस्थिति; (सी) पर्याप्त कारण के बिना की गई प्रविष्टि; (डी)

गलत प्रविष्टि; और (ई) प्रविष्टि में कोई त्रुटि या दोष। इस प्रकार की कार्रवाई "रजिस्टर की शुद्धता" के लिए शुरू की जाती है, जिसे बनाए रखना सार्वजनिक हित में है धारा 46 और 56 के तहत आवेदन रजिस्ट्रार को किया जा सकता है जो राहत देने में सक्षम है। "व्यथित व्यक्ति" कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार को प्रमाणन ट्रेडमार्क से संबंधित रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द करने या बदलने के लिए भी आवेदन कर सकता है। चूंकि हम प्रमाणन ट्रेडमार्क से चिंतित नहीं हैं, जिसके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है, हम इस निर्णय के प्रयोजनों के लिए धारा 69 में आने वाले वाक्यांश "पीड़ित व्यक्ति" की व्याख्या को विचार से बाहर कर सकते हैं।

हमारी राय में वाक्यांश "व्यथित व्यक्ति" है धारा 46 के तहत गैर-उपयोग के आधार पर हटाने का अर्थ रजिस्टर में गलत तरीके से की गई या बची हुई प्रविष्टि को रद्द करने या निकालने या बदलने के लिए धारा 56 में इस्तेमाल किए गए वाक्यांश से अलग है।

बाद के मामले में लोकस स्टैंडी को उदारतापूर्वक सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि यह न केवल उसी व्यापार को करने वाले अन्य व्यक्तियों के हितों के खिलाफ होगा, बल्कि जनता के हित में भी ऐसी गलत प्रविष्टि को हटाया जाएगा। इसी अर्थ में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पॉवेल के ट्रेड मार्क 1894 (11) आरएफसी 4 के मामले में "व्यथित व्यक्ति" को परिभाषित किया:

"... हालांकि इन्हें निस्संदेह उन लोगों द्वारा आधिकारिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए डाला गया था, जिनकी रजिस्टर के सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और केवल एक सामान्य मुखबिर को बाहर करने के लिए, यह निस्संदेह सार्वजनिक हित में है कि उन्हें अनुचित रूप से सीमित नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि यह एक सार्वजनिक कुचेष्टा है कि रजिस्टर पर एक निशान बना रहना चाहिए जो नहीं होना चाहिए, और

जिससे कई लोग प्रभावित हो सकते हैं, जो फिर भी मुकदमेबाजी के जोखिम और खर्च में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे।

जब भी यह दिखाया जा सकता है, जैसा कि यहां, कि आवेदक उसी व्यापार में है जिस व्यक्ति ने ट्रेड मार्क पंजीकृत किया है, और जहां भी ट्रेड मार्क, यदि रजिस्टर पर बना रहता है, या हो सकता है, तो उसके कानूनी अधिकारों को सीमित कर सकता है। आवेदक, ताकि रजिस्टर पर प्रविष्टि के अस्तित्व के कारण वह कानूनी तौर पर वह नहीं कर सके जो, लेकिन रजिस्टर पर निशान के अस्तित्व के लिए, वह कानूनी तौर पर कर सकता था, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास एक व्यथित व्यक्ति के रूप में सुना जाने का अधिकार है।" (जोर दिया)" [अनुच्छेद 30-32]

26. हालाँकि, श्रीमती प्रथिबा सिंह ने 1958 अधिनियम की धारा 107 का हवाला देते हुए दलील दी है कि धारा 125 में गैर-विषयक खंड संदर्भित करता है रजिस्ट्रार की स्वतः प्रेरणा शक्ति सहित संपूर्ण धारा 57 धारा 57(4) में निहित है, और इसलिए ऐसी शक्ति भी प्रायोग नहीं हो सकती यदि धारा 125(1) के तत्व अन्यथा मिलते हैं। हमें डर है कि हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं। धारा 47(4) का उल्लेख किया गया धारा 107 में इस कारण से कि उक्त उपधारा का उल्लेख है उच्च न्यायालय या रजिस्ट्रार को दिए गए रक्षात्मक ट्रेडमार्क के रूप में ट्रेडमार्क का पंजीकरण के आवेदन को रद्द करने के लिए। धारा 47 की अन्य उपधाराएं ऐसे किसी आवेदन का उल्लेख नहीं करतीं बल्कि केवल समझाती हैं कि रक्षात्मक ट्रेडमार्क का क्या मतलब है, और यह इसी कारण से है कि धारा 107 केवल धारा 47(4) को संदर्भित करती है, संपूर्ण धारा 47 को नहीं। हालाँकि, ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 125(1) में, अभिव्यक्ति "धारा 57" का दायरा "और रजिस्टर के सुधार के लिए एक आवेदन" अभिव्यक्ति द्वारा कम कर दी गई है। ऐसे सुधार आवेदन केवल धारा 57(1) और (2) के संदर्भ में हैं, न कि धारा 57(4) के तहत रजिस्ट्रार की स्वतः प्रेरणा शक्ति को नहीं। इसलिए, रजिस्टर की शुद्धता बनाए

रखने के ऊपर दिए गए ठोस कारण के अलावा, धारा 125(1) की शाब्दिक संरचना पर भी, यह स्पष्ट है कि धारा 57(4) को बाहर करना होगा।

27. व्हर्लपूल का मामला, जिस पर अपीलकर्ता के वकील ने दृढ़ता से निर्भर किया है, को उसके अपने तथ्यों के आधार पर समझा जाना चाहिए। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 6 और 7 में इस न्यायालय ने तथ्यों को इस प्रकार निर्धारित किया है:

"28.2.1997 को, अपीलकर्ता ने वर्ग 7 में ट्रेड मार्क "व्हर्लपूल" के नवीनीकरण के लिए फॉर्म टीएम-12 में एक आवेदन दायर किया और रजिस्ट्रार ने अपने आदेश दिनांक 29.07.1997 द्वारा, लगातार तीन अवधियों के लिए नवीनीकरण की अनुमति दी, 22.2.1977, 22.2.1984 और अंत में 22.2.1991। इसके बाद, 8.08.1997 को अपीलकर्ता ने ऊपर संदर्भित वाद संख्या 1705 /1994 में शिकायत में संशोधन के लिए आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन किया, ताकि इसमें मुकदमे में ट्रेड मार्क के उल्लंघन का आधार भी शामिल किया जा सके, लेकिन आवेदन अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसने पहले ही प्रतिवादियों, अर्थात् चिनार ट्रस्ट को जवाब दाखिल करने के लिए दो बार समय दिया है।

इस बीच, चिनार ट्रस्ट ने अपने वकीलों के माध्यम से 10.09.1997 को रजिस्ट्रार को 29.07.1997 को अपीलकर्ता को दिए गए नवीनीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए धारा 56(4) के तहत स्वतः कार्रवाई करने के लिए लिखा और रजिस्ट्रार ने कार्रवाई की। उस अनुरोध पर, 26 सितंबर, 1997 को अपीलकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया। उसे कारण बताने को कहा गया कि क्यों न पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाए। इस नोटिस के खिलाफ अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की जिसे 8.12.1997 को खारिज कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ ही वर्तमान अपील दायर की गई है।" (अनुच्छेद 6 और 7 पर)

28. अंततः, इस न्यायालय का निर्णय उस मामले के तथ्यों पर आधारित हो गया जैसा कि अनुच्छेद संख्या 72 और 73 में बताया गया है।

"वर्तमान मामले में, यह पहले ही ऊपर बताया जा चुका है कि कब ट्रेड मार्क्स के सहायक रजिस्ट्रार ने अपीलकर्ता के विरोध को खारिज कर दिया प्रतिवादी के ट्रेड मार्क के पंजीकरण के आदेश दिनांक 12.8. 1992, द्वारा, इसने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसे 01.02.1993 को स्वीकार किया गया था और तब से 1992 के सी.एम. (मुख्य) 414 के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके बाद, 04.08.1993 को, अपीलकर्ता ने व्यापार से संबंधित प्रविष्टि को हटाने के लिए अधिनियम की धारा 45 और 46 के तहत एक सुधार याचिका दायर की। चिह्नित करें जिसके लिए उत्तरदाताओं को 30.11.1992 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। अपीलकर्ता ने उत्तरदाताओं के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में पासिंग-ऑफ के लिए एक मुकदमा (वाद संख्या 1705/1994) भी दायर किया है जिसमें अपीलकर्ता के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया गया है जिसे खंड उच्च न्यायालय के खंड पीठ ने बरकरार रखा साथ-साथ इस न्यायालय ने भी। उस मुकदमे में, एक संशोधन आवेदन भी दायर किया गया है ताकि अपीलकर्ता के ट्रेड मार्क के उल्लंघन का आधार शामिल किया जा सके लेकिन उस आवेदन का अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि यदि आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो संशोधन आवेदन की तारीख से संबंधित होंगे, यदि वाद की तारीख से नहीं।

उच्च न्यायालय में इन कार्यवाहियों के लंबित होने और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 107 के मद्देनजर, रजिस्ट्रार कानूनी तौर पर प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 56(4) के तहत अपीलकर्ता को कोई स्वतः संज्ञान नोटिस जारी नहीं कर सकता है। पंजीकरण/नवीनीकरण की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। परिणामस्वरूप अपील की अनुमति दी जाती है और अधिनियम की धारा

56(4) के तहत 26 सितंबर 1997 को उप रजिस्ट्रार (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ता अपनी लागत के हकदार होंगे।" [अनुच्छेद 72 और 73 पर]

29 . तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए, इस न्यायालय ने कहा:-
"रजिस्ट्रार को सुधारने के लिए रजिस्ट्रार को धारा 56 द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार की सीमा, हालांकि धारा 107 द्वारा कम कर दी गई है, जो यह प्रावधान करती है कि सुधार के लिए आवेदन, कुछ स्थितियों में, केवल उच्च न्यायालय में किया जाएगा। इन स्थितियों का उल्लेख किया गया है धारा 107 की उप-धारा (1), अर्थात्, जहां पंजीकृत ट्रेड मार्क के उल्लंघन के लिए एक मुकदमे में, पंजीकरण की वैधता पर प्रतिवादी या प्रतिवादी द्वारा सवाल उठाया जाता है, उस मुकदमे में, धारा 30 (1)(डी) जिसमें उन कृत्यों को निर्दिष्ट किया गया है जो उल्लंघन का गठन नहीं करते हैं, और वादी इस बचाव के जवाब में प्रतिवादी के ट्रेड मार्क की वैधता पर सवाल उठाता है। इन स्थितियों में, ट्रेड मार्क के पंजीकरण की वैधता निर्धारित की जा सकती है केवल उच्च न्यायालय द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा नहीं। इस प्रकार धारा 107 कार्यवाही को केवल उच्च न्यायालय में शुरू करने के लिए बाध्य करती है। उन मामलों में रजिस्ट्रार का क्षेत्राधिकार पूरी तरह से बाहर रखा गया है जो धारा 107 के अंतर्गत आते हैं। गौरतलब है कि धारा 107(2) में प्रावधान है कि यदि धारा 46 या धारा 47(4) या धारा 56 के तहत रजिस्ट्रार को सुधार के लिए आवेदन किया जाता है, तो रजिस्ट्रार, यदि वह उचित समझे, उस आवेदन को कार्यवाही के किसी भी चरण में उच्च न्यायालय को संदर्भित कर सकता है।

इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 111 के तहत, ट्रेड मार्क के उल्लंघन से संबंधित एक लंबित मुकदमे में, यदि यह अदालत के ध्यान में लाया जाता है कि वादी या प्रतिवादी के ट्रेड मार्क से संबंधित कोई भी सुधार कार्यवाही रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय

के समक्ष लंबित है उच्च न्यायालय, मुकदमे में कार्यवाही उच्च न्यायालय या रजिस्ट्रार के अंतिम निर्णय तक रोक दी जाएगी। भले ही ऐसी कार्यवाही रजिस्ट्रार या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित न हो, विचारण न्यायालय, यदि प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि वादी या प्रतिवादी के ट्रेड मार्क की अमान्यता के बारे में याचिका तर्कसंगत है, तो वह एक मुद्दा तय कर सकता है और मामले को तीन महीने के लिए स्थगित कर सकता है जो संबंधित पक्ष को रजिस्ट्रार में सुधार के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने में सक्षम बनाता है। यदि तीन महीने के भीतर, संबंधित पक्ष उच्च न्यायालय का रुख नहीं करता है, तो ट्रेड मार्क की अमान्यता के संबंध में याचिका को खारिज कर दिया गया माना जाएगा, लेकिन यदि ऐसे आवेदन पर सुनवाई की गई है, तो मुकदमा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में रोक दिया जाएगा। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष पक्षों को बाध्य करेगा और ट्रेड मार्क की अमान्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय उन निष्कर्षों के संदर्भ में किया जाएगा।

इस पृष्ठभूमि में, वाक्यांश "जिसके समक्ष संबंधित कार्यवाही लंबित है" इस विचार को व्यक्त करने के लिए प्रमुखता से सामने आता है कि यदि कार्यवाही "रजिस्ट्रार" के समक्ष लंबित है, तो यह "न्यायाधिकरण " बन जाता है। इसी प्रकार, यदि कार्यवाही "उच्च न्यायालय", के समक्ष लंबित है तो उच्च न्यायालय को "अधिकरण" के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, हालांकि कुछ मामलों में स्पष्ट रूप से समवर्ती है, परस्पर अनन्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि, यदि कोई विशेष कार्यवाही रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित है, तो कोई अन्य कार्यवाही, जो किसी भी तरह से, लंबित कार्यवाही से संबंधित हो, रजिस्ट्रार द्वारा पहले शुरू की जाएगी और ली जाएगी और उच्च न्यायालय धारा 109 के तहत रजिस्ट्रार के अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यवाही करेगा: यह स्पष्ट है कि यदि कार्यवाही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है तो रजिस्ट्रार अपने हाथ दूर रखेगा और

उन्हें नहीं छूएगा या कोई अन्य कार्यवाही, जो किसी भी तरह से, उन कार्यवाहियों से संबंधित हो सकती है, क्योंकि उच्च न्यायालय, जिसे धारा 3 में निर्धारित क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय होना चाहिए, रजिस्ट्रार के अपीलीय प्राधिकारी होने के अलावा रजिस्ट्रार पर प्रधानता है अधिनियम के तहत सभी मामले। "न्यायाधिकरण " की परिभाषा की कोई अन्य व्याख्या अधिनियम की योजना या उसमें निर्धारित प्रासंगिक पृष्ठभूमि के अनुरूप नहीं होगी और कार्यवाही की बहुलता उत्पन्न करने के अलावा रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालय द्वारा एक ही प्रश्न पर विरोधाभासी निर्णय ले सकती है।।"

[अनुच्छेद 59-62 पर]

30. व्हेलरपूल के मामले में कोई तर्क नहीं दिया गया कि धारा 57(4) यहां ऊपर बताए गए कारणों से धारा 125(1) से स्वतंत्र होगी। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य के विपरीत, उक्त निर्णय को पारित करने के लिए मुकदमे के एक पक्ष ने सुधार के लिए आवेदन किया है। इन दो कारणों से भी उक्त निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। साथ ही, उक्त निर्णय में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि धारा 107(1) कैसे लागू होगी। अकेले पारित करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था- ट्रेडमार्क के उल्लंघन की राहत जोड़ने के लिए एक संशोधन आवेदन लंबित था। शायद इसीलिए इस न्यायालय ने उक्त संशोधन आवेदन का उल्लेख किया और कहा कि यदि इसे मंजूर किया जाता है तो यह मुकदमे की तारीख से ही संबंधित होगा। उक्त मुकदमे में प्रतिवादी स्पष्ट रूप से वादी के संशोधन आवेदन में उल्लंघन की राहत की अनुमति देने से पहले पंजीकृत ट्रेडमार्क की अमान्यता की दलील लेते हुए एक लिखित बयान दायर नहीं कर सकता था। इस कारण से भी हम पाते हैं कि उपरोक्त निर्णय को अधिनियम की धारा 125 और 57 को छूते हुए कानून के किसी भी सिद्धांत को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

31. इसलिए, हमारा विचार है कि, हमारे द्वारा दिए गए कारणों से, खंड पीठ के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।